बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 61 ● नई दिल्ली ● शनिवार 13 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में बिना अनुमति बना बंगला डीडीए ने किया ध्वस्त

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सैनिक फार्म क्षेत्र में स्थित एक बंगले को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की जा रही है, जिसका मकसद अवैध निर्माण और भूमि हड़पने की घटनाओं पर कड़ा संदेश देना है। सूत्रों के अनुसार, यह बंगला बिना अनुमति और नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था। डीडीए की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह कदम शहर में कानूनी कार्रवाई और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

1984 दंगा पीड़ितों को राहत : सीएम रेखा गुप्ता ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी

नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को दिल्ली सरकार ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इससे पहले इसी वर्ष कुछ महीने पूर्व 19 प्रभावित परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस तरह अब तक कुल 55 परिवारों को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह सिर्फ नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन परिवारों के दशकों के लंबे इंतजार और संघर्ष का सम्मान करने की ठोस पहल है। 1984 का दर्द हमारे इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने आगे कहा, यह मदद नहीं, जिम्मेदारी है। यह कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान है। हम बीते कल को याद करते हुए इन परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। गुप्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि आज परिवारों से मिला प्यार और आशीर्वाद उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला पल था। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट सहयोगी एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।1984 के दंगों में हजारों सिख परिवार प्रभावित हुए थे। केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्वास, मुआवजा और अब सरकारी नौकरियों के रूप में प्रभावित परिवारों को राहत और सम्मान देने की कोशिशें जारी हैं। वहीं, पीड़ित के परिवार की सदस्य मंजीत कौर ने कहा, ... यह हमारे लिए एक इमोशनल पल है, क्योंकि हमें रेखा गुप्ता के सपोर्ट से 41 साल बाद इंसाफ मिला है। हम रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा को धन्यवाद देते हैं। यह नौकरी बहुत मायने रखती है। मैं दो साल की थी जब मेरे पिता समेत मेरे परिवार के चार सदस्यों की दंगों में हत्या कर दी गई थी।

राहुल गांधी की बुलाई बैठक से फिर गायब थरूर! कांग्रेस के चीफ व्हिप बोले- नहीं पता वजह

नई दिल्ली। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच अनबन की अफवाहें चल रही हैं। भाजपा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की खबरों के बीच हर कुछ दिनों में तनाव के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि थरूर ने खुद कई बार इन अफवाहों का खंडन किया है, लेकिन एक और उदाहरण राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक में देखने को मिला, जिसमें थरूर शामिल नहीं हुए। पिछले तीन हफ्तों में यह तीसरी कांग्रेस बैठक है जिसमें थरूर अनुपस्थित रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह कांग्रेस के 99 सांसदों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अब तक के उनके प्रदर्शन की समीक्षा की गई और संसद के शीतकालीन सत्र के 19 दिसंबर को समाप्त होने से पहले भाजपा पर अपने हमलों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। थरूर के अनुपस्थित रहने का कारण क्या था? उनके चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी भी बैठक में अनुपस्थित थे। थरूर ने कांग्रेस सत्रों में भाग नहीं लिया। पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) ने कहा कि उन्हें थरूर के मीटिंग में नहीं आने का कारण नहीं पता, जिसके बाद अटकलें और तेज हो गईं। थारूर ने इससे पहले नवंबर में दो बैठकों में भाग नहीं लिया था। पहली बैठक 30 नवंबर को हुई थी, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक रणनीति बैठक थी। अगस्त 2020 में थारूर और अन्य नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने बैठक में भाग लेना नहीं छोड़ा था, बल्कि उस समय वे केरल से उड़ान भर रहे थे। उनके कार्यालय ने पुष्टि की कि वे और उनकी 90 वर्षीय मां पुनर्निर्धारित उड़ान से दिल्ली जा रहे थे, जिसके कारण बैठक में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं था। उस बैठक में कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, केसी वेणुगोपाल भी अनुपस्थित थे। दूसरी बैठक 18 नवंबर को हुई थी और इसमें पार्टी द्वारा विवादास्पद विशेष गहन संशोधन (मतदाता पुनर्सत्यापन) के विरोध पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने की थी। थरूर ने अपनी अनुपस्थिति का कारण खराब स्वास्थ्य बताया। एक दिन पहले वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। केरल के सांसद द्वारा भाषण की प्रशंसा करते हुए किए गए एक ट्वीट ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया का बचपन बचाओ आंदोलन

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ की राजनीति में जहाँ अक्सर देशों के बीच सैन्य तनाव,आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक गठबंधनों और भू-राजनीतिक बदलावों का बोलबाला रहता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है,जिसने अंतरराष्ट्रीय विमर्श को बच्चों की सुरक्षा,डिजिटल बाल–नीति और तकनीकी दुरुपयोग की ओर मोड़ दिया है। यह फैसला किसी युद्ध, प्रतिबंध या व्यापार विवाद से नहीं उपजा,बल्कि यह सीधे-सीधे हमारे परिवारों,हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की मानसिक -सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनियाँ में पहली बार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का निर्णय लेकर एक ऐतिहासिक सामाजिक हस्तक्षेप किया है, जिसने दुनियाँ को चौंकाया भी है और विचार करने पर मजबूर भी किया है।इस फैसले का सीधा असर इंस्टाग्राम,फेसबुक टिकटॉक यूट्यूब, स्नैपचैट, थ्रेड्स और एक्स जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा है। लाखों किशोरों के अकाउंट बंद कर दिए गए है और सख्त प्रावधान किए गए है कि टेक कंपनियों पर 3 करोड़ 20 लाख डॉलर तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वे इस नीति का पालन नहीं करतीं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह कदम केवल एक कानूनी संशोधन या प्रशासनिक आदेश नहीं है,यह एक बचपन बचाओ आंदोलन है जिसे आधुनिक समाज में डिजिटल प्रदूषण, साइबर बुलिंग, मानसिक तनाव, गलत कंटेंट, हिंसक वीडियो और हानिकारक एल्गोरिद्म के बीच बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच माना जा रहा है। साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया का काला सच- बच्चों के जीवन में प्रवेश औरमनोवैज्ञानिक जोखिम इसको समझने की करें तो, दुनियाँ भर की सरकारें, टेक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और अभिभावक लंबे समय से इस चिंता से ग्रसित रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि 10–16 वर्ष की उम्र में बच्चे सोशल मीडिया पर सबसे याद सक्रिय हो रहे है,जहाँ वे अनफ़िल्टर्ड और अक्सर हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आते है। कई बच्चे घंटों तक वीडियो स्क्रॉल करते रहते है और प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम उन्हें उसी तरह के वीडियो दिखाते रहते है, जो ज्यादा व्यूज,ज्यादा क्लिक और कंपनियों के ज्यादा मुनाफे से जुड़े होते है,चाहे वे बच्चों के लिए कितने भी हानिकारक क्यों न हों।मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बच्चे की मानसिकता सबसे अधिक प्रभावित उसी उम्र में होती है जब वह पहचान,व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया में होताहै। हानिकारक ऑनलाइन कंटेंटहिंसक वीडियो, अश्लील सामग्री,साइबर बुलिंग, अवास्तविक सुंदरता मानक और फेक सोशल लाइफ की तुलना बच्चों को गहरे अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, आत्म- असमर्थता और पारिवारिक दूरी की ओर धकेल सकते है। कई अध्ययन साबित करते है कि आज की पीढ़ी किताबों से कम और रील्स से याद सीख रही है, और घरेलू रिश्तों से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सुन रही है। यह खतरे की घंटी है। साथियों बात अगर हम टेक कंपनियाँ बच्चों को क्यों टारगेट करती है? बिजनेस मॉडल का कटु सच इसको समझने की करें तो,ऑस्ट्रेलिया के फैसले के पीछे संभावित एक बड़ा कारण सोशल मीडिया कंपनियों का एल्गोरिदम- आधारित बिजनेस मॉडल हो सकता है? अधिकतम समय तक बच्चे प्लेटफॉर्म पर बने रहें, यह कंपनियों के मुनाफे का मूल तत्व होता है। बच्चों की रुचि तेजी से बदलती है,वे भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते है और वायरल कंटेंट से जल्दी प्रभावित होते है, ऐसे में वे कंपनियों के लिए सबसे आसान उपभोक्ता बन जाते है। एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किए गए होते है कि बच्चे वीडियो देखते रहें, स्क्रॉल करते रहें और प्लेटफॉर्म छोड़ न पाएं। यह डिजिटल व्यसन न सिर्फ उनका समय निगलता है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन से काटकर वर्चुअल दुनियाँ में फंसा देता है। साथियों बात अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बचपन बचाओ आंदोलन, दुनियाँ के लिए उदाहरण इसको समझने की करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में पहली बार लिया गया है। इसके कुछ प्रमुख आयाम है- (1) किशोरों के लाखों अकाउंट बंद-बच्चों की पहचान सत्यापन के लिए कड़े मानदंड लागू कर दिए गए है। (2) 10 सोशल मीडिया ऐप्स पूरी तरहप्रतिबंधित फेसबुक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट, थ्रेड्स सहित सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म 16 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए ब्लॉक कर दिए गए (3) अभिभावकों को सजा नहीं, जिम्मेदारी टेक कंपनियों की ऑस्ट्रेलिया ने यह समझा कि माता- पिता आधुनिकटेक्नोलॉजी की जटिलताओं को हमेशा नहीं समझ सकते। इसलिए दंड सिर्फ कंपनियों पर है। (4) टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना 32 मिलियन डॉलर तक-यह कंपनियों को मजबूर करेगा कि वे बच्चों को टारगेट करने वाली व्यावसायिक रणनीतियाँ बदलें।यह कदम केवल बच्चों की सुरक्षा का मामला नहीं है; यह डिजिटल युग में सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना है।

कई विशेषज्ञ इसे 'डिजिटल फेयर प्ले' का नया युग मान रहे हैं। साथियों बात अगर हम भारत में 35 करोड़ बच्चे,क्या ऐसा आंदोलन जरूरी है? इसको समझाने की करें तो, भारत दुनियाँ का सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ 15 वर्ष तक के लगभग 35 करोड़ बच्चे है, जो किसी भी छोटे देश की कुल आबादी से कहीं ज्यादा है। भारत के माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या सीख रहा है, और किस हद तक सोशल मीडिया के गलत प्रभावों में फंस रहा है। (1)भारत में कई चिंताजनक स्थितियाँ देखी जा रही हैं (2)बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे है। (3) हिंसा और असामाजिक व्यवहार को एंटरटेनमेंट मानने लगे है। (4) पढ़ाई से दूरी बढ़ रही है। (5)नींद, मानसिक स्वास्थ्य औरसामाजिक व्यवहार तेजी से बिगड़ रहे है। (6) इन्फ्लुएंसर्स बच्चों के रोल मॉडल बन गए है। (7) गलत कंटेंट की पहुंच लगातार बढ़ रही है- अगर देखा जाए तो भारत में समस्या ऑस्ट्रेलिया से कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या याद है, मोबाइल पहुंच अधिक है, और डिजिटल साक्षरता अपेक्षाकृत कम है। साथियों बात अगर हम क्या भारत में सोशल मीडिया बैन बचपन बचाओ आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण होगा? इसको समझने की करें तो,यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है,और इसका जवाब सरल नहीं है। भारत एक विशाल, विविध और जटिल लोकतंत्र है, जहाँ सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजगार बाजार और डिजिटल पहुँच का प्रमुख माध्यम है। परंतु यह भी सच है कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत में इस तरह का बैन लागू करना निम्न कारणों से प्रभावी हो सकता है (1)बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा- यदि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, तो उनकी भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक बुद्धि और वास्तविक जीवन के अनुभवों में सुधार होगा। (2) शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव-स्कूलों और घरों में डिजिटल ध्यानभंग कम होगा। बच्चे किताबों, खेलों और वास्तविक गतिविधियों में अधिक समय देंगे। (3)पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे-परिवार के साथ समय बिताने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बच्चों का जीवन डिजिटल आइसोलेशन से बाहर आएगा।(4)टेक कंपनियों पर दबाव-किसी भी प्लेटफॉर्म की कमाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह भारत जैसे बड़े बाजार को महत्व देता है। यदि भारत कड़े नियम लागू करे, तो कंपनियाँ वैश्विक नीतियों को भी बदलने पर मजबूर हो जाएँगी। (5) डिजिटल साक्षरता आंदोलन-इससे भारत में एक व्यापक डिजिटल नैतिकता आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। साथियों बात अगर हम भारत के सामने चुनौतियाँ -क्या यहआसान होगा? इसको समझने की करें तो भारत में इस तरह के प्रतिबंध लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ रहेंगी (1)विशाल जनसंख्या और तकनीकी ट्रैकिंग की कठिनाई(2)डिजिटल पहचान सत्यापन की जटिलता (3) ग्रामीण इलाकों में तकनीकी ढांचा (4) डिजिटल अधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस(5) बच्चों और माता-पिता के बीच विश्वास का मुद्दा (6) विरोध करने वाली टेक कंपनियों की लॉबिंग,लेकिन यह भी सच है कि कोई भी बड़ा सुधार चुनौती- पूर्ण नहीं होता। अगर बच्चों का भविष्य दांव पर हो तो कठिन रास्तों पर चलना भी संभव और आवश्यक होता है। अतःअगर हम अप्रोच पूरे विवरण का अध्ययन करें इसकाविश्लेषण करें तो हम पाएंगे के क्या भारत के लिए यह सही समय है?ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को एक दिशा दिखा दी है कि बच्चों की सुरक्षा में राज्य कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

सम्पादकीय...

कूटनीतिक धुंध में भारत-रूस

रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी दो दिन भारत यात्रा से बहुत संतुष्ट लौटे होंगे। उन पर पश्चिम देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कहा जा रहा है, पर यहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री उनका भव्य स्वागत कर रहे थे। हवाई अड्डे पर नरेन्द्र मोदी ने पुतिन को हग किया, दोनों एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक पहुंचे जहां उनके लिए प्राईवेट डिनर रखा गया। यह कूटनीतिक शिष्टाचार के सामान्य कदम नहीं हैं। जिसे लंदन के गार्डियन अखबार ने मोदी-पुतिन 'ब्रोमांस' अर्थात ब्रिदर-रोमांस कहा है, पश्चिमी राजधानियों में निश्चित तौर पर अखरा होगा। यूक्रेन युद्ध द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुले उल्लंघन के बावजूद पुतिन अपने लोगों को बता सकेंगे कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता कायम है। इस यात्रा के द्वारा भारत रूस के साथ अपने संबंधों को दोहरा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि हमारे पास भी अपने विकल्प हैं। भारत और रूस की 'दोस्ती' के बारे बहुत कुछ कहा जा रहा है। कई टीवी एंकर तो उछल-उछल कर इसकी बात कर रहे थे। यह लोग तब भी उछले थे जब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। हम यह नजरंदाज नहीं कर सकते कि पुतिन की भारत यात्रा चार साल के बाद हो रही थी जबकि दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर बैठक का प्रावधान है। पहलगाम हमले के बाद भी पुतिन का फ़ोन दो सप्ताह के बाद आया था लेकिन इसके बावजूद रूस के साथ हमारे सम्बंध मजबूत रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने लिखा है कि, यह भारत का समय के साथ सबसे परखा और सबसे भरोसेमंद रिश्ता है। यह सम्बंध सोवियत यूनियन के पतन, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी, चीन के उत्थान, भारत और चीन के बीच टकराव, यूक्रेन युद्ध और अब डोनाल्ड ट्रम्प के भारत पर धावे के बीच कायम रहा है, पर समय आ गया था कि इसे फिर से परिभाषित किया जाए, जो पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत कर भारत ने कर भी दिया है और दुनिया ने नोट भी किया है। अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर जिस विश्वास के साथ हम पिछले 25 सालों से चल रहे थे उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। भारत पहले भी रूस से तेल आयात करता रहा है, पर बाइडेन सरकार ने इसे भारत की मजबूरी समझते हुए बहुत आपत्ति नहीं की थी, पर ट्रम्प ने भारत पर अतिरिक्त 25फीसदी टैरिफ़ लगा दिया है। चीन और ईयू सब रूस से तेल आयात करते है, पर उन्हें इस अतिरिक्त टैरिफ़ से अलग रखा गया। अमेरिका खुद रूस से आयात कर रहा है। ट्रम्प का आरोप है कि 'भारत पुतिन की वॉर-मशीन को तेल खरीद कर फंड कर रहा है। पुतिन ने भी एक इंटरव्यू में सवाल किया है कि अगर अमेरिका रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि ट्रम्प भारत को आर्थिक जख्म पहुंचाना चाहते है। पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ़ और असीम मुनीर का स्वागत किया। मुनीर की प्रशंसा के पुल बांधे गए। उसे दोबारा व्हाइट हाउस बुलाया गया, यह जानते हुए कि भारत इस व्यक्ति से नफ़रत करता है और पहलगाम हमले का मुजरिम समझता है लेकिन इससे ऊपर पुतिन को निमंत्रण एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमारी विदेश नीति हम तय करेंगे, तुम नहीं। बीबीसी ने तो कहा भी है कि यह 'रणनीतिक स्वायत्तता का खेल है'। आज़ादी के बाद जब भारत बहुत कमजोर था तब भी गुट निरपेक्ष की नीति हमारी स्वायत्तता की अभिव्यक्ति थी। अब तो भारत मजबूत देश बन चुका है। हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तय करेंगे कि कौन हमारा मित्र है, कौन नहीं। पुतिन की यात्रा एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बयान है कि हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए नहीं। पश्चिम, विशेष तौर पर अमेरिका की नीति प्रतीत होती है कि जो हमारे साथ नहीं, वह हमारा विरोधी है। भारत यह नीति रद्द कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे साथ बहुत नीच व्यवहार किया है। हमने उन्हें संदेश भेज दिया है कि न हम रूस के साथ व्यापार बंद करेंगे और न ही उन्हें अपने से दूर करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इज्जत बढ़ी है। जिस डोनाल्ड ट्रम्प के आगे ईयू, जापान, कोरिया, यूके आदि ने समर्पण कर दिया उसके आगे भारत ने झुकने से इंकार कर दिया। ट्रम्प की प्रतिक्रिया क्या होती है यह देखना होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के साथ ऐसा घटिया व्यवहार क्यों किया? अमेरिका के रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने इसके लिए 'चापलूसी और रिश्वत' को जिम्मेवार ठहराया है। यह 'रिश्वत' ट्रम्प परिवार को पाकिस्तान से मिली है और वह ही देश बार-बार ट्रम्प को नोबेल सम्मान के लिए मनोनीत करता रहा है। इस सारे खेल में दो और खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज को प्रभावित कर रहे है। यूक्रेन और चीन। जब पुतिन ने चार वर्ष पहले यूक्रेन पर हमला किया था तब उन्हें आशा नहीं थी कि यह युद्ध इतना लम्बा चलेगा। रूस ने इसकी बहुत कीमत चुकाई है, पर पश्चिम को भी समझ आ गई है कि रूस को उसकी अपनी सीमा के अंदर हराना असम्भव है। यूक्रेन मारा गया और यह स्पष्ट हो गया कि वह रूस को पराजित नहीं कर सकता और पश्चिम रूस से पूरे युद्ध के लिए तैयार नहीं, पर इस टकराव के कारण भारत अनावश्यक सजा भुगत रहा है। मास्को जा कर नरेन्द्र मोदी कह चुके है कि यह युद्ध का युग नहीं है। अब फिर पुतिन की यात्रा के दौरान कहा गया कि भारत तटस्थ नहीं है, शान्ति के पक्ष में है। पता नहीं कि इसका पुतिन पर कितना असर होगा। उन पर युद्ध समाप्त करने का अधिक से अधिक दबाव डाला जाना चाहिए। लेकिन भारत की यही समस्या नहीं है। भारत चिन्ता से देख रहा है कि पश्चिम की नीति ने रूस को चीन के साथ सम्बंध घनिष्ठ करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों देश कह रहे है कि उनकी पार्टनरशिप की कोई सीमा नहीं। अतीत में रूस और चीन के बीच टकराव हो चुका है, पर इस वक्त दोनों अमेरिका के विरोध का सामना कर रहे है। चीन की नजर भी पुतिन की भारत यात्रा पर थी। कई चीनी टिप्पणीकार कह रहे है कि एक सीमा के बाद रूस भारत की पार्टनरशिप चीन के हितों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आखिर में भारत और चीन विरोधी है और नियंत्रण रेखा अभी भी तनाव ग्रस्त है।

कुत्ते का ड्रामा

'ड्रामा' शब्द शायद इस माह की शुरुआत में शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से संसद की केंद्रीय थीम रहा है, इस शब्द का प्रयोग भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से काफी उदारता से किया गया। शुरुआत के लिए, इस शीतकालीन सत्र के अपने पारंपरिक पूर्व-सत्र संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था ड्रामा करने के लिए बहुत सी जगहे है। जिन्हें ड्रामा करना है, वे कहीं और करें। यहां डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद के समक्ष मौजूद मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि सरकार पिछले 11 वर्षों से लगातार संसदीय शिष्टाचार और संसदीय प्रणाली को रौंदती रही है। खड़गे ने कहा, भाजपा को अब इस ध्यान-भटकाने वाले ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए और जनता के वास्तविक मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। एक अन्य स्तर पर, एक कुत्ते को लेकर भी काफी ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जब एक कुत्ते को लेकर संसद पहुंचीं, तो एक भाजपा सदस्य ने उचित दस्तावेज न होने पर आपत्ति जताई। बेतुकापन किस स्तर तक पहुंचा है या इसमें कौन अधिक खराब दिखा-यह आकलन करना कठिन है, लेकिन एक बात स्पष्ट है- संसद और उसके लिए चुने गए प्रतिनिधि एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए है, लेकिन इस कुत्ते-कांड का संदर्भ समझना आवश्यक है, जिस तरह यह घटनाक्रम सामने आया। हंगामा तब शुरू हुआ जब चौधरी की कार एक कुत्ते के साथ संसद भवन परिसर में दाखिल हुई। चौधरी के अनुसार, उन्होंने एक आवारा कुत्ते को उठाया था और उसे पशु-चिकित्सक के पास ले जा रही थीं। एक कहानी यह है कि उनका चालक उन्हें संसद में उतारने के बाद कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। दूसरी कहानी यह है कि उन्होंने संसद आते समय रास्ते में एक आवारा कुत्ते को बचाया और उसे सीधे पशु-चिकित्सक के पास ले जा रही थीं। एक और कहानी यह भी है कि कार में मौजूद कुत्ता चौधरी का अपना पालतू था और उसे महज नाटकीयता के लिए संसद लाया गया और नाटकीयता आगे भी जारी रही। जब सत्तारूढ़ पार्टी ने चौधरी पर ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा कि सरकार को जानवर पसंद नहीं है। यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा- इनकी समस्या क्या है?

यह इतना छोटा है, क्या यह काटेगा? संसद में बैठे लोग काटते है, कुत्ते नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क से कुत्ता बचाने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। वाह सरकार, उन्होंने ट्वीट किया। दरअसल, जब उन्हें विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की धमकी दी गई, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कुत्ते की आवाज की नकल करते हुए कहा- भौं, भौं। मामला छोड़ने के मूड में न होते हुए भाजपा ने कहा कि चौधरी संसद का मजाक बना रही है और तमाशा कर रही है, और दोषी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2018 की ओर लौटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में चौधरी की तेज हंसी का मजाक उड़ाया था। राज्यसभा में, मोदी की एक टिप्पणी पर रेणुका जोर से हंस पड़ी थीं, जिसके बाद सभापति ने संयम बरतने को कहा।

इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें रोका न जाए- रामायण सीरियल के बाद, हमें इस तरह की हंसी सुनने का सौभाग्य आज ही मिला है। भले ही प्रधानमंत्री ने रामायण के किसी चरित्र का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि संदर्भ रावण की बहन शूर्पणखा का था, लेकिन चौधरी कोई असहाय नायिका नहीं है। उन्होंने भी नाम लेकर कटाक्ष किए है। अकाली दल की हरसिमरत बादल, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थीं, को याद करें। कुछ वर्ष पहले, आरोप है कि चौधरी ने उन्हें कचरा कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे भाड़ में जाएं, और बादल की टिप्पणी को पॉलिटिकल ड्रामा बताकर खारिज कर दिया था। चाहे वह कुत्ते का प्रकरण हो, शूर्पणखा-संदर्भ हो या कचरा टिप्पणी मूल तथ्य यही है कि संसद की मर्यादा और गरिमा गिर चुकी है, बल्कि कहना चाहिए कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, और इसका दोष किसी एक पार्टी या एक सांसद पर नहीं डाला जा सकता, यह सामूहिक विफलता है। उतना ही अभूतपूर्व यह भी है कि सदन के भीतर नेता-विशेष के समर्थन में नारे लगाए जाते है। इसे समझें तो पता चलता है कि भाजपा शासन में जब भी प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रवेश करते है, मोदी, मोदी के नारे गूंज उठते है। आश्चर्य की बात है कि इन्हें रोकने के लिए सभापति की ओर से कोई निर्देश या हस्तक्षेप नहीं होता। हालात ऐसे दिखाई देते है कि यदि संभव होता तो सभापति भी इस मोदी समर्थक नारेबाजी में शामिल हो जाते। मूल विषयों पर आया जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस संस्था का मजाक बना दिया है जिसे कभी अत्यंत सम्मान प्राप्त था। यह एक संवैधानिक पवित्र स्थान था जहां मुद्दों पर चर्चा, वाद-विवाद और मतभेद होना स्वाभाविक माना जाता था। आज यह हंगामों और उसके बाद होने वाले स्थगनों तक सीमित रह गया है। अक्सर पूरा सत्र ही इस कारण व्यर्थ चला जाता है क्योंकि विपक्षी सांसद सदन को चलने नहीं देना चाहते। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि जहां पहले यह माना जाता था कि संसद चलेगी, आज सुचारू कार्यवाही एक दिवास्वप्न बन गई है। आंकड़े इसकी पुष्टि करते है। उदाहरण के लिए, 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 के बीच हुए मानसून सत्र में निर्धारित समय का दो-तिहाई हिस्सा बाधाओं में नष्ट हुआ। इसका प्रभाव प्रश्नकाल पर भी पड़ा, जिसमें लोकसभा केवल 23फीसदी और राज्यसभा मात्र 6फीसदी निर्धारित समय तक ही काम कर सकी। कई विधेयक भी बिना चर्चा के पारित किए गए। एकमात्र सकारात्मक पहलू बजट सत्र रहा, जिसमें लोकसभा की उत्पादकता 111फीसदी और राज्यसभा की 112फीसदी रही-और प्रश्नकाल भी अपेक्षाकृत बेहतर चला। 2024 के बजट सत्र में भी यही रुझान दिखा था, लेकिन ये हाल के वर्षों के अव्यवस्थित व्यवहार से अलग कुछ दुर्लभ अपवाद भर है।

सरकार को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए

भारतीय जनता पार्टी, जो तीसरी बार सत्ता में है और पिछले कुछ महीनों में लगातार चुनाव जीतकर मजबूत होती जा रही है, उससे कम से कम असुरक्षा की उम्मीद तो की ही जा सकती है। फिर भी, केंद्र में पार्टी की लीडरशिप वाली सरकार आमतौर पर विपक्ष और खासकर विपक्ष के टॉप नेताओं के साथ डील करते समय छोटी सोच दिखा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में उनके भारतीय समकक्ष द्वारा राष्ट्रपति भवन में ऑफिशियल डिनर के इनविटेशन को मना करना इसका एक उदाहरण है। न तो लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी और न ही राज्यसभा में विपक्ष के लीडर मल्लिकार्जुन खरगे को ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया था। यह एक ट्रेडिशन रहा है कि सभी पार्टियों के नेताओं को लेकिन निश्चित रूप से दोनों सदनों में विपक्ष के लीडर को, ऐसी ऑफिशियल दावतों में हाई टेबल पर इनवाइट किया जाता है। यह इशारा भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। मजे की बात है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि संविधान दिवस के मौके पर हुए इवेंट के दौरान ऐसी सोच देखने को मिली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को एक साथ स्टेज शेयर करते हुए प्रिएंबल पढ़ते देखना अच्छा लगा। यह भी एक लंबी परंपरा रही है कि विजिट करने वाले हैड ऑफ स्टेट्स अपने ऑफिशियल विजिट के दौरान टॉप विपक्षी नेताओं से मिलते है। पुतिन के विजिट के दौरान ऐसी कोई मीटिंग न होने का कारण यह बताया जा रहा है कि विजिटिंग डेलीगेशन को अप्वाइंटमेंट और विजिट का यात्रा कार्यक्रम तय करना होता है। हालांकि, ऐसे विजिट का यात्रा कार्यक्रम आपसी सलाह-मशविरे के बाद तय किया जाता है। दुर्भाग्य से, पिछले एक दशक से ज्यादा समय से देश की राजनीति में भाजपा की मजबूत स्थिति के बावजूद उसके नेताओं और विपक्ष के बीच अभूतपूर्व कड़वाहट है। एक-दूसरे को बुरा-भला कहना, राजनीतिक विरोधियों को अपमानित करने की कोशिश करना, बेबुनियाद आरोप लगाना और एक-दूसरे का मजाक उड़ाना अब आम बात हो गई है न कि कोई अपवाद। जहां राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेता 'चौकीदार चोर है' या 'वोट चोरी' जैसे नारे लगा रहे है, जिनका मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा उन्हें अपमानजनक तरीके से 'पप्पू' कह रही है और आम तौर पर विपक्षी नेताओं को नीचा दिखा रही है। ऐसे कई और उदाहरण है जिनमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करते समय मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं। हालांकि, इन व्यक्तिगत हमलों पर आधिकारिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों या मामलों के दौरान विचार नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन द्वारा विपक्षी नेताओं को न्यौता न देना जबकि कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर को आमंत्रित किया गया जो विदेश मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख है लेकिन जो फिलहाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर है, इससे बचा जाना चाहिए था। यह और भी ज्यादा अवांछनीय था क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क किया था।

समतामूलक विचारधारा निर्माण करती कविताएं

कवि दलित-बहुजन समाज के उत्थान के लिए उन तमाम असमानताओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों के कारणों का विनाश चाहता है जो उनके गरिमामय नागरिक जीवन जीने के रास्तों में अवरोधक बनते हैं। कवि को जातीय भेद पर होने वाले अमानवीय व्यवहार कतई स्वीकार नहीं। बदलाव के पक्ष में कवि ने कविता पक्ष में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह का अनाचार बर्दाशत नहीं करेंगे। अब हम गूंगे नहीं हैं कविता में कवि की इन्हीं भावनाओं का आवेग देखा जा सकता है- हम गूंगे नहीं रहे अब / दर्द समेटने में सक्षम हैं/ चिल्ला सकते हैं/ बदला ले सकते हैं। अपमान तिरस्कार का/। बनकर खड़ी है। राजेश कुमार बौद्ध बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अनुयायी हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा समतामूलक समाज-निर्माण के लिए संघर्ष की विचारधारा है। वैचारिक संघर्ष को हताशा-निराशा की नहीं, साहस-बल की जरूरत है।। सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के उत्पीड़न से जुझते हुए अपनी पहचान के लिए संघर्ष का लम्बा सफर भावुकता से नहीं, वैज्ञानिक विचारधारा से करना पड़ेगा। कवि दम तोड़ती मेरी आवाज अम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुसरण में बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास है जो कभी हार न मानेगी मेरी आवाज़ मिशन की ओर अग्रसर है। कवि का यह सृजनात्मक-सफ़र निरन्तर आगे बढ़ता रहे।

राजेश कुमार बौद्ध की मार्मिक रचनाएँ- पुत्री, सिर्फ यादें, जलन, बेबसी, एक युग का अंत है अफसोस, प्रेमचंद, गांधी के भक्त, मेरे नंगेपन, पक्ष, अब हम गूंगे नहीं रहे अब, दम तोड़ती मेरी आवाज, अब हम गूंगे नहीं है। इन रचनाओं की गहन समीक्षा निम्नलिखित है, और हमें आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी ये सभी रचनाएँ समाज को एक नई ऊर्जा देंगी और बीते हुए पल की ताजगी दी गई है। कवि की कविताओं में साहित्य और समाज का यथार्थवादी सामंजस्य स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी भाषा अत्यंत सरल, सीधी और आम जन-जीवन से जुड़ी हुई है, जो भावनाओं को बिना किसी आडंबर के सीधे पाठक के हृदय तक पहुँचाती है। कवि ने अपने समाज के प्रति होने वाले अन्याय और अत्याचार की समस्या को उठाया है। उन समस्याओं पर सवाल खड़े किए है। समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की तलाश में है।

समस्याओं के प्रति खोखली दया, सहानुभूति, सांत्वना नहीं चाहता, न्याय चाहता है। देश को आजाद हुए पचहत्तर वर्ष बीत चुके लेकिन दलितों के जीवन में गरीबी और लाचारी है। अशिक्षा का अंधकार है। जातीय दुर्भावनाओं की हवाएं इतनी तेज हैं जिसकी चपेट में कहीं बेटियां हवस का शिकार है। राजेश कुमार बौद्ध की कविताएं अफसोस दलित समाज के पढ़े-लिखे लोगों की आत्मकेन्द्रीयता की भावना पर चिन्ता जाहिर करती है। प्रेमचंद तथा गांधी के भक्त- तथाकथित प्रगतिशील लेखकों की प्रगतिशीलता पर सवाल खड़े करती है। मुंशी प्रेमचंद, कर्मचंद गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर तीनों समकालीन थे। प्रेमचंद ने अपनी रचनात्मकता में गांधीवादी विचारधारा को प्रभावात्मक रूप से प्रचारित किया लेकिन डॉ. अम्बेडकर के दलितों- बहुजनों को सामाजिक, राजनैतिक आदि अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए आंदोलनों का संकेत मात्र भी जिक्र नहीं किया। डॉ. अम्बेडकर के कार्यों के प्रति यह उपेक्षा भाव प्रेमचंद की दलित चेतना को प्रश्नचिह्नित करता है। कवि ऐसे किसी भी साहित्य को दलित साहित्य मानने का विरोध करता है जो दलितों में चेतना नहीं, चिन्ता जगाती हो। उनके प्रति केवल दया, सहानुभूति जगाती हो। चेतना का अर्थ है चिन्तन करना, सजग सचेत करना है। उत्पीड़न की स्थितियों पर सवाल उठाने और उन सवालों को खत्म करने के रास्ते सुझाना है। कवि ने तथाकथित प्रगतिवादी लेखकों की दलित चेतना की षड्यंत्रकारी घुसपैठ को उजागर किया है। पुत्री- यह कविता पिता और पुत्री के रिश्ते की सबसे गहरी और अनकही सच्चाई को सामने लाती है। आप पुत्री के लिए पिता को दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड बताते है, जो रिश्ते की भावनात्मक नींव को दर्शाता है। यह स्वीकारोक्ति कि पिता के न रहने पर पुत्री की हिम्मत भी मर जाती है, अत्यंत मार्मिक है। यह कविता न केवल प्रेम को बल्कि पुत्री के लिए मायके में हक और सुरक्षा की भावना को भी परिभाषित करती है। प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है का प्रयोग रिश्ते की अपार गहराई को दर्शाता है। सिर्फ यादें- आपकी यह रचना बीते हुए कल के ग्रामीण और सादगीपूर्ण जीवन के प्रति गहरी नॉस्टेल्जिया (पुरानी यादों) को दर्शाती है। गर्मियों की रातों में आंगन में चारपाई, जुगनू पूरी रात टिम-टिमाकर और तारे एक-दूसरे से बातें कर रहे हों जैसे बिंब (इमेजरी) पाठक को सीधे शांत, Anmol भरे माहौल में ले जाते हैं। आपकी कविता आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन पर एक टिप्पणी है कि हमने फोन और भागदौड़ में वो ताजगी, वो सुकून खो दिया है, जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गया है। जलन- यह एक आत्मविश्वासी रचना है,जो लेखक के संघर्ष और सफलता के प्रति उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह कविता साहित्यिक जगत की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि सफलता अक्सर अपनों और गैरों, दोनों से ईर्ष्या का कारण बनती है। अंतिम पंक्तियाँ एक लेखक के जीवट और आत्मविश्वास को दर्शाती है- राजेश तुम चुप चाप / आगे बढ़ते रहो / खूब लिखते रहो। यह नकारात्मकता को रचनात्मक ऊर्जा में बदलने का संदेश देती है। बेबसी- यह रचना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना से ओत-प्रोत है। ट्रेन के जनरल डिब्बे को भारत का वर्तमान और भविष्य देखने का माध्यम बनाना एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यह बिंब हमारे देश की आर्थिक असमानता और मेहनतकश लोग तथा वोट का इस्तेमाल करने वाले वर्ग के बीच के गहरे अंतर को स्पष्ट करता है। यह कविता केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि उस वर्ग की बेबसी, भूख और दर्द का अहसास कराती है, जो देश की इमारतें बनाते है, जबकि दूसरा वर्ग उनका हिस्सेदारी का 90फीसदी भाग बड़े आराम से निगल रहा है। एक युग का अंत है- यह कविता संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन और शहरीकरण के कारण भौतिक एवं भावनात्मक दूरियों को दर्शाती है। आपने मिट्टी के मकानों और संयुक्त परिवारों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया। बंटवारे का नाम लेना ही गुनाह और पाप था यह दर्शाता है कि पहले रिश्ते मकान से ज्यादा मजबूत थे। यह रचना एक सांस्कृतिक परिवर्तन पर शोक व्यक्त करती है, जहाँ घर कच्चे जरूर थे / जिगर लोगों का फौलाद था की तुलना में आज घर पक्के होने पर भी रिश्तों में भी दरारें पड़ गईं। देश की आधी अबादी औरतों की है लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति आज भी पारम्परिक दमनात्मक रीतियों की शिकार है। दमनात्मक परम्पराओं से पीड़ित औरतें भी दलित-बहुजन समाज की औरतों के जातीय उत्पीड़न के विरोध में नहीं आती। जातीय भेद की पक्षधरता के कारण पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता को बढ़ावा देती है। कविता मेरे नंगेपन में कवि इन्हीं भावनाओं को स्पष्ट करते हैं-जिन महिलाओं ने / गायों को अपनी माँ बताया है। माँ पूजा करती हैं। गायों को बचाने के लिए सड़कें पर उतरती हैं। मेरी नग्नता ने / शायद उन्हें चोट नहीं पहुँचाई/। कवि दलित-बहुजन समाज के उत्थान के लिए उन तमाम असमानताओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों के कारणों का विनाश चाहता है जो उनके गरिमामय नागरिक जीवन जीने के रास्तों में अवरोधक बनते है। कवि को जातीय भेद पर होने वाले अमानवीय व्यवहार कतई स्वीकार नहीं। बदलाव के पक्ष में कवि ने कविता पक्ष में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह का अनाचार बर्दाशत नहीं करेंगे। अब हम गूंगे नहीं है कविता में कवि की इन्हीं भावनाओं का आवेग देखा जा सकता है- हम गूंगे नहीं रहे अब / दर्द समेटने में सक्षम है/ चिल्ला सकते है/ बदला ले सकते है। अपमान तिरस्कार का/। बनकर खड़ी है। राजेश कुमार बौद्ध बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अनुयायी है। अम्बेडकरवादी विचारधारा समतामूलक समाज-निर्माण के लिए संघर्ष की विचारधारा है। वैचारिक संघर्ष को हताशा-निराशा की नहीं, साहस-बल की जरूरत है।। सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के उत्पीड़न से जुझते हुए अपनी पहचान के लिए संघर्ष का लम्बा सफर भावुकता से नहीं, वैज्ञानिक विचारधारा से करना पड़ेगा। कवि दम तोड़ती मेरी आवाज अम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुसरण में बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास है जो कभी हार न मानेगी मेरी आवाज़ मिशन की ओर अग्रसर है। कवि का यह सृजनात्मक-सफ़र निरन्तर आगे बढ़ता रहे। बहुजन साहित्य में काव्य का यकीनन स्वागत होगा। हार्दिक शुभकामनाएँ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एन्क्ल. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

एसआईआर सर्वेः राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर दूर की शंकाएं

मुरादाबाद।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की विधानसभा वार प्रगति एवं अन्य जरूरी जानकारी दी उन्होंने कहा कि 13 दिसम्बर को प्रत्येक बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे और राजनीतिक दलों द्वारा नामित बीएलए का सहयोग प्राप्त करते हुए मतदाता सूची के अनुसार एएसडी (एब्सेंट, सिफ्टेड, डूब्लीकेट) नामों का पुनः

आज बूथों पर उपस्थित रहेंगे बीएलओ

सत्यापन किया जाएगा ताकि यदि त्रुटिवश किसी मतदाता का नाम शामिल होने से छूट रहा हो तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नाम शामिल कर लिया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि एएसडी (एब्सेंट, सिफ्टेड, डूब्लीकेट) मतदाताओं के रूप में चिन्हित नामों की सूची बूथ पर मौजूद बीएलओ के पास उपलब्ध रहेगी साथ ही मुरादाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आमजन की सुविधा और जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि आयोग स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं कि वास्तविक मतदाता का नाम किसी भी दशा में नहीं छूटना चाहिए साथ ही नियमानुसार प्रत्येक मतदाता का सत्यापन भी हो जाए। उन्होंने बताया कि नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भी बीएलओ से फार्म-6 प्राप्त किया जा सकता है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाता के परिजन भी नियमानुसार गणना पत्र भरकर जमा कर सकते हैं परंतु नए मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित फार्म-6 को स्वयं आवेदक को भरकर जमा करना होगा। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एसआईआर को लेकर शंकाओं का समाधान भी किया और कहा कि राजनीतिक दल अपने बूथवार नामित बीएलए के माध्यम से एएसडी के रूप में चिन्हित नामों का पुनः सत्यापन कराने में सहयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी, 2026 के आधार पर चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए संशोधित तिथियों के अनुसार 26 दिसम्बर, 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है। निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर, 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसम्बर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर, 2025 से 21 फरवरी, 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम, एसडीएम सदर राम मोहन मीणा, 'वाइंट मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी गण एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण मौजूद रहे।

पीडीए की एकसूत्र-एकजुट भावना एक नया इतिहास लिखेगीः भारती

मुरादाबाद।

समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती आज देर शाम वन्देमातरम एक्सप्रेस ट्रेन से मुरादाबाद स्टेशन पहुँचे यहाँ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने स्टेशन पर उनका अभिनन्दन एवं जोरदार नारेबाजी के बीच फूलमाला पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। स्वागत पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने सभी पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ संगठन की शक्ति जब जुड़ती है और जब शोषित-वंचित, दमित समाज एक साथ उठ खड़ा होता है तो 'मूक क्रांति' मुखर हो उठती है। हमारे हम सबके आह्वान और अपील पर, पीडीए प्रहरियों के सद्प्रयासों से पीड़ा के एकसूत्र में बंधे पीडीए समाज ने अपना वोट बनवाकर चुनाव जीतने की मज़बूत बुनियाद बना ली है, इसी पर 'पीडीए सरकार' की इमारत बुलंद होगी। हर पीड़ित, दुखी और अपमानित अब एकजुट होकर 'अपनी पीडीए सरकार' बनाने के लिए कटिबद्ध भी है और संकल्पबद्ध भी। हमें पीडीए की एकता का ये सूत्र हमेशा याद रखना है 'जो पीड़ित, वो पीडीए!' पीडीए = 'प्रेम, दया और अपनेपन' के अर्थ में एक भावनात्मक संबंध है। पीडीए की एकसूत्र-एकजुट भावना एक नया इतिहास लिखेगी। भारतीय संस्कृति की 'वसुधैव कुटुंबकम्' की विराट वैश्विक भावना मिलने-जुलने और मेल-मिलाप से ही फलीभूत होती है। दुनियाभर में आपसी एतबार से भाईचारा और भाईचारे से अमन-चैन आता है, जिससे हर किसी के लिए खुशहाली लानेवाली तरक्की मुमकिन होती है। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ये राजनीति का नहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, वेदप्रकाश सैनी,जिला प्रवक्ता धर्मेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, राजू यादव,तहजीब आलम, एम,पी. सिंह आदि मौजूद रहे।

शिव सैनिकों ने किया कुन्दरकी विधायक का स्वागत

मुरादाबाद।

कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का शिव सेना के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नन्हें चौधरी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि शिव सेना के साथ हमारा बहुत लंबे समय से गठबंधन रहा हैबीच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ दिया , जिस कांग्रेस ने हमेशा बाला साहब ठाकरे का विरोध किया। तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाला साहब के पदचिन्हों पर चलने वाली शिव सेना पुनः भाजपा के साथ जुड़ी। इस समय हमारे गठबंधन की महाराष्ट्र में जनकल्याणकारी सरकार चल रही है। शिव सेना शिंदे गुट बाला साहब ठाकरे की नीतियों पर चल रहा है। नन्हें चौधरी को बधाई देते हुए विधायक कुंदरकी ने कहा कि अपने कुछ समय पूर्व ही शिव सेना की कमान संभाली है, आपसे भी अपेक्षा है राष्ट्रवाद के पथ पर चलते हुए संगठन को चलाएंगे। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा मनोज गुप्ता एडवोकेट, जिला अध्यक्ष नन्हें चौधरी, प्रदेश सचिव रामप्रसाद प्रजापति, जिला प्रभारी मनोज ठाकुर, दीपक चौधरी, विकास चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी, अकुल आदि उपस्थित रहे।

कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि शिव सेना के साथ हमारा बहुत लंबे समय से गठबंधन रहा है बीच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ दिया , जिस कांग्रेस ने हमेशा बाला साहब ठाकरे का विरोध किया। तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाला साहब के पदचिन्हों पर चलने वाली शिव सेना पुनः भाजपा के साथ जुड़ी।

डॉक्टरों को किया सम्मानित

मुरादाबाद। जाट महिला महासभा की ओर से डा. रंजना सिंह (स्त्री रोग विशेषज्ञ) जो नॉर्मल डिलीवरी के जानी जाती है एवं डा. रिषभ सिंह (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) बेहतरीन युवा सर्जन और डा0 कोमल सिंह (स्त्री रोग विशेषज्ञ) को पटका पहनाकर एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अखिल उत्तर प्रदेश जाट महिला महासभा की प्रदेश अध्यक्ष डा0 सगीता चौधरी, जिला अध्यक्षा ममता चौधरी, उपाध्यक्ष सविता सिंह, रीता ढाका समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। जाट महिला सभा समाज की विभूमियों को उत्कृष उत्कृष कार्य के लिए सम्मानित करती रही है।

नर्सें ही असली योद्धाः रि. ब्रिगेडियर डॉ. अमिता

टीएमयू के रिद्धि- सिद्धि भवन में आयोजित लैंप लाइटिंग सेरेमनी में ली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ

मुरादाबाद।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की सेवानिवृत ब्रिगेडियर डॉ. अमिता देवरणी ने नर्सिंग स्टुडेंट्स से कहा, नर्सें असली योद्धा होती हैं। कठिन परिस्थितियों, युद्ध क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं या व्यस्त अस्पतालों में नर्सें ही सबसे पहले और अंतिम समय तक रोगी के साथ रहती हैं। नर्सिंग पेशा सम्मान, साहस और सेवा से भरा हुआ है। उन्होंने नर्सिंग स्टुडेंट्स से हर परिस्थिति में अनुशासन बनाए रखने, रोगी के दर्द को समझने, टीमवर्क की क्षमता विकसित करने, तनावपूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने की कला सीखने और पेशेवर नैतिकता को कभी न छोड़ने की सलाह दी। डॉ. अमिता ने कहा, आज आप जो दीप अपने हाथों में थामे हुए हैं, वे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि आपके भीतर की सेवा-भावना का प्रतीक है। इस प्रकाश को कभी मंद न होने दें। डॉ. देवरणी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के तीर्थंकर पार्श्वनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग- टीपीसीओएन, अमरोहा की ऑथ सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं।

इससे पूर्व ब्रिगेडियर डॉ. अमिता ने बतौर मुख्य अतिथि, आरएके नर्सिंग कॉलेज, दिल्ली की पूर्व प्राचार्य प्रो. हरिंदर गोयल ने बतौर विशिष्ट अतिथि, टीएमयू के वीसी प्रो. वीके जैन, निदेशक गवर्नेंस डॉ. नीलिमा जैन, सीटीएलडी के डायरेक्टर प्रो. पंकज कुमार सिंह आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित करके रिद्धि-सिद्धि भवन में ऑथ सेरेमनी का शंखनाद किया। दूसरी ओर नर्सिंग स्टुडेंट्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अतिथियों का मन मोह लिया। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज की डीन प्रो. एसपी सुभाषिनी, टीपीसीओएन की प्राचार्या प्रो. श्योली सेन आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। नर्सिंग कॉलेज की डीन प्रो. एसपी सुभाषिनी ने नर्सिंग स्टुडेंट्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ दिलाई। शपथ में स्टुडेंट्स ने हाथ में दीप लिए प्रतिज्ञा दोहराई, हम मानवता की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित रखेंगे। पेशेंट के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता का सम्मान करेंगे। नैतिकता, अनुशासन और स'चाई से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के संग-संग अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट रखेंगे। टीएमयू के कुलपति प्रो. वीके जैन ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। डॉक्टर उपचार करते हैं लेकिन नर्सें रोगी के पास रहकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं। नर्सिंग पेशा एक ऐसा कर्तव्य है, जहां आपके प्रत्येक निर्णय में किसी रोगी का जीवन छिपा हो सकता है। प्रो. सुभाषिनी ने कहा, नर्सिंग प्रतिज्ञा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह आपके चरित्र, कर्तव्य और पेशेवर पहचान का आधार है।

अमित शाह की भविष्यवाणी होने लगी सच! कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व से माँगने लगे हिसाब

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो दिन पहले ही लोकसभा में अपने भाषण में कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा वार करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी की लगातार हार का हिसाब एक दिन कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता ही आलाकमान से मांगेंगे। देखा जाये तो अमित शाह की यह भविष्यवाणी राजनीति में सिर्फ एक बयान नहीं थी, आज की स्थिति देखकर लगता है कि वह सीधे कांग्रेस के भीतर फैलते असंतोष को भांप चुके थे। हुआ भी वैसा ही। ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पत्र आ गया, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए और उसी दिन शशि थरूर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक से अनुपस्थित रहे, मानो पार्टी के भीतर उबलता लावा अब सतह पर फूटने लगा हो। हम आपको बता दें कि ओडिशा के पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकिम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सौ साल पुरानी विरासत हाथ से फिसल रही है और इसका कारण है नेतृत्व में स्पष्टता की कमी, संगठनात्मक ढीलापन और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। मुकिम ने मांग की है कि पार्टी की बागडोर ऐसे नेता के हाथ में दी जाए जो युवा, ऊर्जावान और प्रभावी जनसंपर्क क्षमता रखता हो। उन्होंने इस संदर्भ में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि पार्टी को अब नए नेतृत्व की सख्त जरूरत है। हम आपको बता दें कि मुकिम के पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व न तो चुनावी धरातल समझ पा रहा है, न संगठन को मजबूत कर पा रहा है। यही कारण है कि हालिया उपचुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय झेलनी पड़ी। कई नेता और कार्यकर्ता दिशाहीन महसूस कर रहे हैं और पार्टी धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खोती जा रही है। उधर बीजेपी ने इस मौके को हाथों-हाथ लेते हुए दावा किया कि कांग्रेस में अब खुलकर दो गुट बन चुके हैं यानि -टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका-। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह पत्र कांग्रेस के भीतर की उथल-पुथल का सिर्फ एक नमूना है; असंतोष का असली स्वरूप इससे कहीं बड़ा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मोहभंग बढ़ रहा है और वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि यह कांग्रेस के गिरते मनोबल, बिखरते नेतृत्व और टूटती संगठनात्मक आत्मा का चार्जशीट है। जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई, जो दशकों तक सत्ता में रही, वह पार्टी आज अपने ही नेताओं के पत्रों, नाराज कार्यकर्ताओं और दिशाहीन नेतृत्व के कारण राजनीतिक खाई की ओर तेजी से फिसल रही है। कांग्रेस का संकट चुनावी नहीं, अस्तित्व का संकट है। नेतृत्व का सवाल अब सिर्फ रणनीति का मामला नहीं रहा; यह पार्टी की पहचान और भविष्य को सीधे चुनौती दे रहा है। जब एक पूर्व विधायक लिखता है कि सदियों की विरासत हाथ से निकल रही है, तो समझ लेना चाहिए कि बीमारी बहुत गहरी है।

2027 में होने वाली जनगणना के लिए कैबिनेट ने दी 11718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी

नई दिल्ली।

- दो चरणों में होगी जनगणना
- 30 लाख लोग जनगणना को देंगे अंजाम
- कोयले से जुड़ी सुधार नीति को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को तीन बड़े फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सेंसस 2027 को लेकर फैसला हुआ. इसके लिए 11718 करोड़ का बजट पास हुआ. दूसरा कोल यानी एनर्जी सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है. तीसरा किसानों से जुड़ा फैसला लिया गया है.

भारत में होगी पहली डिजिटल जनगणना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2027 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी. जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना. केंद्रीय मंत्री ने बताया, पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा. यह एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगा.

सेंसस के लिए जाति बताना जरूरी नहीं

केंद्रीय मंत्री ने बताया, सेंसस को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन आएगा. इसमें जाति आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. सेंसस को लेकर डेटा प्रोटेक्शन का काफी ध्यान रखा गया है. जाति बताना जरूरी नहीं है, कोई चाहे तो वह नहीं भी बता सकता है. सिर्फ एग्रीगेटेड डेटा को पब्लिश किया जाएगा. माइक्रो डेटा को पब्लिस नहीं किया जाएगा.

कोल उत्पादन को लेकर सरकार का फैसला

यूनियन कैबिनेट ने कोयले की नीलामी के लिए नई व्यवस्था 'कोल सेतु' को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोल सेतु यानी कोल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म हो रही है. इंपोर्टेड कोल से निर्भरता कम होने के कारण हम 60 हजार करोड़ रुपये बचा रहे हैं. 2024-25 में 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है. रेल और कोल एक तरीके से पार्टनर है. डोमेस्टिक जितने पावर प्लांट है उसमें रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक क्रिएट हो चुके हैं.

किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए पिसाई वाले खोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और गोल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है. एनएएफईडी और एनसीसीएफ इसके लिए नोडल एजेंसियां होंगी.

योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ

देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत

*किसानों को बीज से बाजार तक मिलेगी सुविधा

*किसानों की आय को तीन गुना करने का लक्ष्य

बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21 फीसदी योगदान देता है। वह बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सीएम योगी शुक्रवार को हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव में पद्मश्री और प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा के फार्म पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम योजनाएं चलाई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ने बड़े स्तर पर किसानों को राहत दी है। सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ-साथ यदि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियों, फल उत्पादन और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को अपनाने से सीमित भूमि पर भी शानदार उत्पादन संभव है। सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी प्रगति के बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार हर जिले में किसान प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और आधुनिक मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आप बस काम करिए, मजदूर आपके पीछे खड़ा, यूपी के एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों से मुलाकात की और उन्हें जनता तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की सलाह दी। यह मुलाकात संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर हुई। अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायकों को जनता से अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए और उन्हें सांसदों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जागरूक करना चाहिए। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि आप लोग सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान दें। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह पुरानी पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है और चुनाव नजदीक आने पर काम करने का दिखावा करती है। इसके विपरीत, एनडीए जनता के लिए चौबीसों घंटे काम करता है। उन्होंने कहा कि हम लगातार काम करते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं और उपलब्धियों का जनता के बीच पर्याप्त प्रचार नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ से लोकसभा में 80 सांसद जाते हैं। 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उत्तर प्रदेश की 36 सीटें जीतीं। इनमें से भाजपा के 33 सांसद हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल (सोनेलाल) के क्रमशः दो और एक सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं। वे 2014 के लोकसभा चुनावों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने 7, लोक कल्याण मार्ग आवास पर सभी छह सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। एक्स पोस्ट में कहा कि आज शाम लोक कल्याण मार्ग स्थित 7 नंबर के होटल में एनडीए सांसदों को रात्रिभोज पर आमंत्रित करना बेहद सुखद अनुभव रहा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

'वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की धज्जियां उड़ा दीं - राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्ष ने संसद में 'वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की धज्जियां उड़ा दीं और गृह मंत्री अमित शाह मानसिक रूप से परेशान थे। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूरा तंत्र 'वोट चोरी में शामिल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''हमने संसद में हुई 'वंदे मातरम् और मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा में उनकी (सत्तापक्ष) धज्जियां उड़ा दीं। अमित शाह सदन में मानसिक रूप से परेशान थे, बहुत दबाव में थे।

उन्होंने सदन में गाली तक दे दी। इसके पीछे कारण है कि वह और उनका पूरा सिस्टम 'वोट चोरी में शामिल था। इससे पहले राहुल गांधी ने, निचले सदन के कांग्रेस सदस्यों के साथ शुक्रवार को बैठक की, जिसमें उन्होंने वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान 'वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान पार्टी सांसदों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अब इन दोनों विषयों पर दबाव में है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के साथ संसद भवन परिसर में यह बैठक की, जिसमें पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि भी दी गई।

पाटिल का 90 वर्ष की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। बैठक के बाद कांग्रेस सूत्रों ने बताया, ''नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार वंदे मातरम् और चुनाव सुधारों के मुद्दों पर दबाव में है तथा हमारे सांसदों ने चर्चा के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने 'पीटीआई-वीडियो से कहा, ''यह नियमित तौर पर होने वाली बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष हर सत्र में सांसदों के साथ बैठक करते हैं। कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। सांसदों के विचारों को सुनते हैं।

कुछ गड़बड़ हो रही है..., करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उठाए मद्रास हाई कोर्ट पर सवाल?

नई दिल्ली। करूर भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग और सुनवाई के तरीके में कुछ गलत हो रहा है और इस पर जवाब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की एक रिपोर्ट मिली। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले में पक्षकार भी बना दिया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, हमें यह देखना होगा। टीवीके की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। टीवीके की याचिका सिर्फ रोड शो के लिए दिशानिर्देश चाहती थी, लेकिन चेन्नई बेंच ने सीधे एसआईटी जांच का आदेश दे दिया। यह आदेश मदुरै बेंच के पहले के आदेश से उलटा था, जिसमें सीबीआई जांच से मना किया गया था। दो अलग-अलग आदेशों ने सुप्रीम कोर्ट को चिंतित किया और उसने हाई कोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। यह मामला 27 सितंबर को TVK की रैली में हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उसे सुनवाई चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सीबीआई जांच वाली रोक हटाई जाए और एक सदस्यीय जांच आयोग (न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन) को काम जारी रखने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वह पहले यह समझना चाहता है कि आयोग क्या करेगा, इसलिए इस मुद्दे पर बाद में फैसला होगा। अभी कोर्ट सिर्फ यह देखना चाहता है कि मद्रास हाई कोर्ट में केसों को कैसे लिस्ट किया और सुना जा रहा है।

महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट का भारी निवेश, एआई हब, 45 हजार लोगों के लिए रोजगार

मुंबई।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की और भारत के पहले एआई-संचालित प्लेटफॉर्म महाक्राइमओएस एआई का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने फेसबुक पर लिखा कि महाराष्ट्र ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है।

#AITourMumbai में सत्य नडेला से मिलकर बेहद खुशी हुई, जहां हमने महाक्राइमओएस एआई का अनावरण किया - भारत का पहला एआई-संचालित प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है। 23 पुलिस स्टेशनों से 1100 तक विस्तार; नागपुर से राज्यव्यापी स्तर तक, महाराष्ट्र नागरिक सुरक्षा के लिए एआई-संचालित शासन को बढ़ावा दे रहा है! उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं। राज्य सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्लेटफॉर्म से अपनी पुलिस को लैस करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। महाक्राइमओएस एआई नामक एआई-संचालित प्रणाली का अनावरण मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर में किया गया, जो भारत के डिजिटल पुलिसिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबरआई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के विशेष प्रयोजन वाहन मार्वल और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर (आईडीसी) के सहयोग से विकसित महाक्राइमओएस एआई, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और ओपनएआई तकनीकों का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों को तेजी से ट्रैक करने और हल करने में मदद करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म पहले से ही नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में चालू है और राज्य के सभी 1,100 पुलिस स्टेशनों में इसका विस्तार करने की योजना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनहित के लिए नैतिक और जिम्मेदार एआई हमारा मूलमंत्र है। एआई में दक्षता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और प्रत्येक नागरिक के लिए वास्तविक सुगम जीवन प्रदान करके परिवर्तन लाने की शक्ति है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा सहयोग जटिल साइबर अपराध चुनौतियों को हल करने से शुरू हुआ, लेकिन इसकी क्षमता कहीं अधिक है। हम इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करके एक अधिक प्रभावी, नागरिक-केंद्रित राज्य का निर्माण करना चाहते हैं।

लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा, कहा- हम क्या करने वाले हैं इस पर बात हो

नई दिल्ली। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण पर हम क्या करने वाले है इस पर बात हो, न कि आरोप- प्रत्यारोप हो।

इस मुद्दे पर हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है।

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उसका अगले चार-पांच साल का प्लान क्या है और उन्होंने इस योजना को सदन के पटल पर रखने की मांग की। अधिकांश बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने जोर दिया कि यह कोई वैचारिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के लोगों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने सदन में सभी सदस्यों से सहयोग करने की अपील की, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत होंगे कि वायु प्रदूषण से हो रहे नुकसान पर हम सभी सहयोग करना चाहेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि प्रदूषण का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय, सरकार और विपक्ष को बैठकर इस मुद्दे पर समाधान ढूंढना चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर देश के हर शहर के लिए प्रदूषण से निपटने की अलग-अलग और विशिष्ट योजनाएं बनाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पहल करने की भी अपील की। राहुल गांधी ने कहा, मेरा मानना है कि बेहतर यही होगा कि हम यह न कहें कि आपने क्या नहीं किया और न ही आप यह कहें कि हमने क्या नहीं किया, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत के लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं।

नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ीं

नई दिल्ली। नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71फीसदी के स्तर पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25फीसदी पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस-मछली,

रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71 फीसदी पर पहुंची, अक्टूबर में ये 0.25 फीसदी पर थी

मसालों, फ्यूल और लाइट की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। सरकार ने शुक्रवार, 12 दिसंबर को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई के बास्केट में लगभग 50फीसदी योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है। इसकी महीने-दर-महीने की महंगाई माइनस 5.02फीसदी से बढ़कर माइनस 3.91फीसदी हो गई है। नवंबर महीने में ग्रामीण महंगाई दर - 0.25फीसदी से बढ़कर माइनस 0.10फीसदी हो गई है। वहीं शहरी महंगाई 0.88फीसदी से बढ़कर 1.40फीसदी पर आ गई है।

अमृतसर में हाई अलर्ट, 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी संगठन का मेल सामने आया

पंजाब। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके चलते छात्रों को स्कूलों से बाहर निकाला गया और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने अमृतसर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक बयान में कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को संदिग्ध ईमेल मिले हैं। प्रत्येक स्कूल में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात किया गया है और तोड़फोड़ रोधी जांच जारी है। साइबर पुलिस स्टेशन ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है। इस बीच, अमृतसर पुलिस

आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि स्कूलों को मिली बम की धमकियां झूठी थीं और मामले की जांच जारी है। भुल्लर ने कहा कि अमृतसर जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और परिसरों को सुरक्षित कर लिया गया... धमकियां झूठी निकलीं... जांच जारी है। इस बीच, एडीसीपी-2, सिरिवेनेला ने बताया कि अधिकारियों ने तोड़फोड़ रोधी जांच की है और चिंता की कोई बात नहीं है। दस से बारह स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं। हमने सभी स्कूलों में तोड़फोड़ रोधी जांच की है। चिंता की कोई बात नहीं है; यह सिर्फ एक झूठी कॉल थी। हम पता लगा रहे हैं कि ये ईमेल किसने भेजे हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले लक्ष्मी नगर स्थित दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके चलते स्कूल को खाली कराया गया। यह धमकी सुबह करीब 10:40 बजे फोन पर मिली, जिसमें दावा किया गया था कि लवली पब्लिक स्कूल के अंदर एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया है। सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को दी गई। इसके जवाब में कई अग्निशमन गाड़ियां, बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और पुलिस दल मौके पर भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया और परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया।